गरीब कल्याण मिशन के क्रियान्वयन की मंत्रिमंडल ने दी स्वीकृति

■ शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति ■ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। प्रदेश को वर्ष 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी निर्णायक कदम उठाते हुए मंत्रि-परिषद ने गरीब कल्याण मिशन के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी।

मिशन का उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित वर्गों का आर्थिक उत्थान करते हुये उनकी आय को न्यूनतम आय के स्तर तक लाना है। गरीब कल्याण मिशन संयुक्त रूप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से क्रियान्वित किया जायेगा। गरीब कल्याण मिशन मुख्यत: तीन घटकों यथा बहु-आयामी गरीबी इण्डेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। बहुआयामी गरीबी इण्डेक्स के मुख्य बिन्दु महिलाओं और बच्चों का पोषण सुनिश्चित करना, शिशु मृत्यु दर कम करना, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, माध्यमिक कक्षा तक के छात्रों की स्कूल में उपस्थिति, भोजन पकाने के लिए समुचित ईंधन उपलब्धता, स्वच्छता, पेयजल उपलब्धता, विद्युत कनेक्शन, आवास निर्माण, परिवारों के पास संसाधन उपलब्धता, बैंक खाता की उपलब्धता के साथ वित्तीय समावेश में सुधार किया जायेगा। मंत्रि-परिषद द्वारा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत प्रदेश के शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दी है। सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना मिशन मोड में वर्ष 2025-26 तक की जाना है। जिला स्तर पर 20 किलोवॉट और उससे अधिक क्षमता वाले शासकीय भवनों को एग्रीगेट कर निविदा के माध्यम से रेस्को पद्धति या कैपेक्स मोड में म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के विभिन्न घटकों में घरेलू क्षेत्र में सोलर रूफ टॉप की स्थापना के साथ ही प्रदेश के शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना की जाना है।

डायल-100 सेवा के द्वितीय चरण के लिए 1565 करोड़ की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा एकीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र (डायल-100) सेवा के द्वितीय चरण अप्रैल-2025 से सितम्बर-2030 तक (5 वर्ष 6 माह) के संचालन के लिए 1200 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल (एफआरवी) के साथ कुल अनुमानित राशि 1565 करोड़ रूपये की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गयी। मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना को आगामी 2 वर्षों (वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26) में निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। योजना में ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज उत्पादन/ मत्स्यपालन, ग्रामीण तालाबों में झींगा पालन, मत्स्यपालकों को प्रशिक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड (ब्याज अनुदान), स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना, एकीकृत सूचना प्रणाली का विकास, राज्य मछली महाशीर का संरक्षण आदि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राशि 100 करोड़ रूपये राज्यांश स्वीकृत किया गया है।

पुलिस बैण्ड की स्थापना के लिए नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश के जिलों में पुलिस बैण्ड की स्थापना के लिए कुल 932 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 10 निरीक्षक बैण्ड, 38 उप निरीक्षक बैण्ड, 72 सहायक उप निरीक्षक बैण्ड, 170 प्रधान आरक्षक बैण्ड और 642 आरक्षक बैण्ड के पद शामिल है।

औद्योगिक क्षेत्र की अपार संभावनाओं की भूमि है शहडोल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शहडोल औद्योगिक क्षेत्र की अपार संभावनाओं की भूमि है। सहयोग और साझेदारी के साथ क्षेत्रीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये 16 जनवरी को यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाला है।

इसमें उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ नीति संवाद और नवाचार साझा किये जायेंगे। कॉन्क्लेव में 4 हजार से अधिक प्रतिभागी और 2 हजार से अधिक उद्योगपति शामिल होंगे। डॉ. यादव कॉन्क्लेव में 28 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन करेंगे। इन इकाइयों में 570 करोड़ रूपये का निवेश और 2600 रोजगार का सृजन होगा। कॉन्क्लेव में टोरेंट पॉवर द्वारा 1600 मेगावाट थर्मल प्लांट के लिए 18 हजार करोड़ रूपये का निवेश संभावित है। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री देश के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन चर्चा करेंगे। साथ ही निवेशकों के साथ 3 सेक्टोरल सत्र भी होंगे। कॉन्क्लेव के शुभारंभ सत्र में मुख्य सचिव अनुराग जैन मध्यप्रदेश के उद्योग दृष्टिकोण पर प्रकाश डालेंगे और उद्योग विभाग की एक साल की उपलब्धियों पर फिल्म का प्रदर्शन होगा।

अधिकारियों द्वारा प्रेजेन्टेशन

प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन और एमएसएमई राघवेन्द्र कुमार सिंह प्रदेश में निवेश के अवसरों, अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के अवसरों, अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संजय दुबे आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम में अवसरों, प्रमुख सचिव खनिज संसाधन उमाकांत उमराव खनन एवं खनिज क्षेत्र में अवसरों और प्रमुख सचिव पर्यटन शिव शेखर शुक्ला पर्यटन क्षेत्र में अवसरों का प्रस्तुतिकरण देंगे।

कॉन्क्लेव में प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा अपने अनुभव साझा किये जायेंगे। कॉन्क्लेव में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला और एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर व्यापार प्रोत्साहन के लिए बिजनेस प्रमोशन सेंटर और ट्रेड एसोशियन एवं शासकीय विभागों के प्रदर्शनी स्टॉल लगेंगे।

जापान बनेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कंट्री पार्टनरः डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष में प्रवेश पर उनको समर्पित मंत्रि-परिषद की अगली बैठक 24 जनवरी को महेश्वर में होगी।

ग्वालियर मेला और विक्रमोत्सव उज्जैन में मोटरयान करों में छूट के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ज्ञान (गरीब-युवा-अन्नदाता और नारी शक्ति) पर ध्यान के ध्येय वाक्य के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्रदेश में आरंभ स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की बधाई देते हुए डॉ. यादव ने कहा कि शीघ्र ही गरीब कल्याण मिशन का क्रियान्वयन भी प्रदेश में आरंभ होगा। मुख्यमंत्री बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश प्रोत्साहन की दिशा में अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में होने जा रही है। भोपाल में 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जापान भी कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान यात्रा प्रस्तावित है।

सेना दिवस पर दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 जनवरी को सेना दिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सेना दिवस देश के वीर जवानों के शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। डॉ. यादव ने वीर सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि देशवासियों को अपनी सेना और सैनिकों के

मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने मुख्यमंत्री जाएंगे जापान

साहस पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन भारतीय सेना की वीरता से परिपूर्ण गाथाओं और कर्तव्य निष्ठ पर गर्व करने का दिन है। मातृभूमि की रक्षा के लिये हमारे जवानों की नि-स्वार्थ सेवा और समर्पण पर देशवासियों को गर्व है। डॉ. यादव ने कहा कि मैं देश की सेना के जवानों को सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने मौसम और हालातों पर काबू पाते हुए देश की रक्षा और आन-बान के लिए अपने परिवार से ऊपर अपने कर्तव्य पथ पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं।

स्व. नंदा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्व. गुलजारीलाल नंदा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारत रत्न स्व. नंदा सदैव एक सच्चे कर्तव्यनिष्ठ और आदर्श राजनेता के रूप में याद किए जाते हैं। डॉ. यादव ने कहा कि स्व. नंदा ने दो बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में दायित्वों का निर्वहन किया। श्री नंदा 1932 में सत्याग्रह आंदोलन के लिए जेल गए। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में 1942 से 1944 तक जेल में रहे। श्री नंदा ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उन्होंने केंद्रीय श्रम, गृह एवं रोजगार मंत्री के रूप में भी अपने दायित्वों का निर्वहन किया।

गेहूँ खरीदी के लिए 20 जनवरी से पंजीयन

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री जोशी के साथ हुई वीसी में दी जानकारी

भोपाल(काप्र)।

गेहूँ खरीदी के लिये किसानों का ऑनलाइन पंजीयन आगामी 20 जनवरी सोमवार से शुरू होगा। गेहूँ खरीदी के लिये 4 हजार उपार्जन केन्द्र बनाये जायेंगे। गत वर्ष 3800 उपार्जन केन्द्र बनाये गये थे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी। श्री जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गेहूँ उपार्जन की तैयारियों की राज्यवार समीक्षा कर रहे थे।

श्री जोशी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लायें। किसानों को गेहूँ उपार्जन के बाद जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू करें। उन्होंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल में जिम्मेदार लोगों की ड्यूटी लगायें। श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष उपार्जन केन्द्रों पर गेहूँ की मेकेनाइज्ड क्लीनिंग के लिये मशीन लगाने का प्रस्ताव है। इससे खराब गेहूँ की खरीदी रुकेगी। उन्होंने समितियों को दिये जाने वाले कमीशन की राशि बढ़ाने की बात कही। मंत्री श्री राजपूत ने गेहूँ और चावल के द्वितीय त्रैमास के प्रावधानित अनुदान देयक एवं फोर्टिफाइड राइस आदि मदों की लंबित राशि शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने बताया कि उपार्जन के संबंध में उत्तर प्रदेश में की जा रही कार्रवाई के अध्ययन के लिये एक टीम लखनऊ भेजी जा रही है। इस दौरान आयुक्त खाद्य श्री सिबि चक्रवर्ती व अधिकारी उपस्थित थे।

मप्र में कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन आज से

भोपाल (काप्र)।

32 संगठनों के कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन, पुरानी पेंशन और पदोन्नति समेत 48 मांगें

प्रदेश में कर्मचारी संगठनों का बड़ा आंदोलन गुरुवार से शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 32 कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति समेत 48 मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौपेंगे। आंदोलन के पहले चरण में सभी जिला मुख्यालयों पर कर्मचारी एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। मोर्चा के अध्यक्ष एमपी द्विवेदी के अनुसार, आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए सभी संभागों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये प्रभारी 2 फरवरी को अपने-अपने संभाग मुख्यालय पर मीडिया से चर्चा कर आंदोलन की आवश्यकता को स्पष्ट करेंगे। मोर्चा के संयोजक महेंद्र शर्मा और एसबी सिंह ने बताया कि फिलहाल चार चरणों के आंदोलन की घोषणा की गई है। इन चरणों के बाद सरकार का रुख देखा जाएगा। अगर सरकार ने मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, तो हड़ताल का निर्णय लिया जा सकता है। आंदोलन में मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ, पशुपालन परिक्षेत्र अधिकारी कर्मचारी संघ और तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ समेत कई प्रमुख संगठन शामिल हैं।

आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों को सुगम तरीके से हितलाभ करें सुनिश्चितःशुक्ल

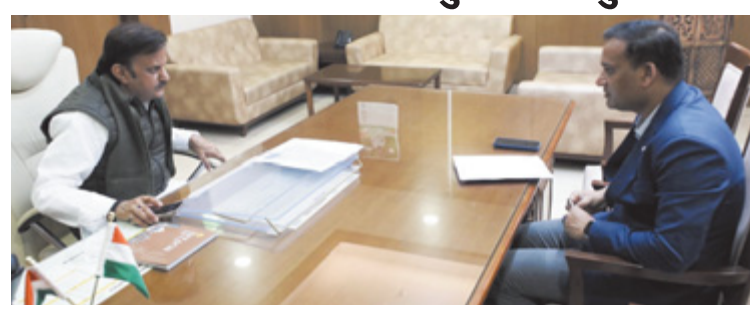

भोपाल(काप्र)।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों को सुगम तरीके से हितलाभ सुनिश्चित किया जाये। उन्हें अनावश्यक तकलीफ़ों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है और यह एक वरदान है। इसके विधिवत् क्रियान्वयन के लिए सतत निगरानी रखें।

श्री शुक्ल ने मंत्रालय में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन और सशक्तीकरण कार्यों की समीक्षा की और समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री शुक्ल ने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। सीईओ आयुष्मान भारत योजना और संचालक (प्रोजेक्ट) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग डॉ. योगेश भरसट ने उप मुख्यमंत्री को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 20 लाख हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और 38 लाख से अधिक उपचार सेवाओं से हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। वहीं, 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड (वयवंदना कार्ड) की प्रगति में मध्यप्रदेश शीर्ष पर है। अब तक मध्यप्रदेश में 12,11,527 वयवंदना कार्ड वितरित किए गए हैं।

नई आबकारी नीति पर विपक्ष की घेराबंदी

भोपाल (काप्र)।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नई आबकारी नीति लागू होने के पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार तो पुरानी सरकार से भी शराब को लेकर आगे निकल गई है।

अब शराब दुकान के 100 मीटर के दायरे में मिनी बार खोलने की तैयारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शराब दुकानें खोले जाने को लेकर सरकार अपनी नई नीति ला रही है। वर्तमान में शराब की दुकानों में ही अवैध रूप से चल रहे अहातों को लेकर सवाल उठा है। पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से चल रहे इन अहातों को लेकर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। शिवराज सरकार इन अहातों को शराबबंदी के पहले कदम के रूप में बंद करके गई थी। हालांकि सरकार ने नई नीति का ड्राफ्ट भी अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन पटवारी ने कहा कि चर्चा है कि जो अहाते शिवराज सरकार के कार्यकाल में बंद किए थे, उनकी जगह मोहन सरकार अब परमिट रूम खोलने की तैयारी कर रही है। यानी परमिट लो और खूब शराब पिलाओ। उन्होंने यह भी कहा कि शराब दुकान के 100 मीटर के दायरे में मिनी बार के तौर पर लाइसेंस दिए जाने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है, जहां बैठकर लोग शराब पीएंगे। राजस्व बढ़ाने के चक्कर में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 211 नई दुकानें खोले जाने का प्रस्ताव इस आबकारी नीति में रख सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में 2005 में 2270 शराब दुकानें थीं, लेकिन अब 2025 में 3 हजार 605 दुकानें हो गई हैं। शराब दुकानों के ठेके भी 20 प्रतिशत ज्यादा लाइसेंस फीस के साथ रिन्यू होंगे, यानी सरकार अपना राजस्व बढ़ाएगी। पटवारी का कहना है कि धार्मिक नगरों में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की जो घोषणा की जा रही है, वह केवल इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हैं। इसमें बड़े स्तर पर वसूली और कमीशनबाजी होगी। नशे से पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं और सरकार को इस बात को समझना चाहिए।

स्पेशल खबर *श्रीमती गौर की मौजूदगी में सहमति पत्र पर हुए हस्ताक्षर...*

आधुनिक तकनीक से होगा घूमंतु समुदायों का शैक्षणिक विकास

भोपाल(काप्र)।

विमुक्त, घूमन्तु और अर्ध घूमन्तु कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्ध घुमन्तु समुदाय के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए सरकार लगातार नए नवाचार कर रही है।

श्रीमती गौर की मौजूदगी में विमुक्त, घुमन्तु और अर्ध घुमन्तु कल्याण विभाग और सशक्तिकरण सामाजिक संस्था के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। श्रीमती गौर ने कहा कि एमओयू से विमुक्त, घुमन्तु और अर्ध घुमन्तु समुदायों के विद्यार्थियों को अक्षर एवं अंक ज्ञान से शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाया जावेगा। यह कार्य विमुक्त, घुमन्तु और अर्ध घुमन्तु कल्याण विभाग की

ओर चलाए जा रहे छात्रावासों में कमजोर अपेक्षित समुदायों के पहली से पांचवी कक्षा तक के विद्यार्थियों को विभाग से बिना आर्थिक मदद लिये सशक्तिकरण सामाजिक संस्थान द्वारा स्वयं के मद से किया जावेगा। संस्थान की ओर से नियुक्त महिला शिक्षा साथी चिंपल ऐप की सहायता से स्केलेबल मूलभूत साक्षरता कक्षायें लेंगी।

सहमति पत्र पर विमुक्त, घुमन्तु और अर्ध घुमन्तु कल्याण विभाग की ओर से विमुक्त, घुमन्तु और अर्ध घुमन्तु कल्याण विभाग के संचालक नीरज वशिष्ठ की उपस्थिति में, उप संचालक डॉ. दीप्ति सुदीप कोटस्थाने और संस्था की ओर से सुश्री श्रुति श्रीवास्तव ने हस्ताक्षर किए। ये कक्षाएं स्कूल समय के पश्चात लगाई जायेंगी। संस्थान ऐप के माध्यम से इन विद्यार्थियों की विषय को समझने की क्षमता की रिपोर्ट से विभाग को समय-समय पर प्रस्तुत करेगा। इसके साथ विद्यार्थियों को बाल अधिकार एवं पॉक्सो एक्ट के संबंध में जागरूक किया जायेगा। पहले चरण में विभाग द्वारा संचालित चार छात्रावासों में प्रारंभ किया जा रहा है। इसके जरिए प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के बीच मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन -फाउंडेशनल लिट्रेसी एंड न्यूमरेसी) के साथ कौशल विकास किया जा सके।